

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Wednesday, 19 August 2026

अटल सेतु रोड डैमेज मामले मे ठेकेदार पर 1 करोड़ का जुर्माना, जांच रिपोर्ट ने खोली लापरवाही की पोल

Publisher

Published on 19 Sep 2025



गोवा में स्थित देश के सबसे लंबे नदी पुलों में से एक **अटल सेतु** इन दिनों सुर्खियों में है। हाल ही में सामने आई सड़क क्षति की घटनाओं ने न केवल यात्रियों को परेशान किया बल्कि सरकार को भी कार्रवाई करने पर मजबूर कर दिया।

सरकारी जांच रिपोर्ट में सामने आई लापरवाही के बाद संबंधित ठेकेदार पर **1 करोड़ रुपये का जुर्माना** लगाया गया है। यह कार्रवाई उस बढ़ती नाराजगी के बीच हुई है, जिसमें लोग सवाल उठा रहे थे कि इतने महत्वपूर्ण और महंगे प्रोजेक्ट में इस तरह की खामियां आखिर कैसे सामने आ सकती हैं।

अटल सेतु : गोवा की लाइफलाइन

गोवा की राजधानी **पणजी** में मांडवी नदी पर बना अटल सेतु राज्य की लाइफलाइन माना जाता है। यह पुल लगभग 5.1 किलोमीटर लंबा है। इसे 2019 में जनता को समर्पित किया गया था। इसका नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री **अटल बिहारी वाजपेयी** के सम्मान में रखा गया। इस पुल ने न केवल पणजी और उत्तरी गोवा के बीच आवागमन आसान किया, बल्कि पर्यटन और व्यापार को भी नई गति दी।

दरारे और गड्ढों ने बढ़ाई चिंता

बीते महीनों में अटल सेतु पर **सड़क की ऊपरी परत में दरारे और गड्ढे** दिखाई देने लगे। यात्रियों ने सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया में इस मुद्दे को उठाया।

बारिश के मौसम में इन गड्ढों की स्थिति और बिगड़ गई, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया। लोगों का कहना था कि जिस पुल पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए, वह कुछ सालों में ही खराब कैसे हो गया।

जांच में खुली लापरवाही

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए **पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD)** ने जांच करवाई। रिपोर्ट में सामने आया कि सड़क निर्माण में मानक गुणवत्ता का पालन नहीं किया गया। ड्रेनेज सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा था, जिसके कारण पानी जमा होकर सड़क को नुकसान पहुंचा। कुछ हिस्सों में सस्ते और घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया गया।

इन खामियों को देखते हुए विभाग ने ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराया और उस पर **1 करोड़ रुपये का जुर्माना** लगाया।

सरकार का सख्त रुख

गोवा सरकार ने साफ किया कि **सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी**। PWD ने ठेकेदार को चेतावनी दी है कि भविष्य में अगर इसी तरह की समस्या दोहराई गई, तो ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। ठेकेदार को यह भी कहा गया कि वह तुरंत मरम्मत कार्य शुरू करे और अगले महीने के भीतर सड़क को पूरी तरह दुरुस्त करे।

विपक्ष और जनता की प्रतिक्रिया

अटल सेतु के मामले पर विपक्षी दलों ने भी सरकार पर सवाल उठाए। विपक्ष का कहना है कि इतनी बड़ी परियोजना में निगरानी की कमी रही। अगर समय रहते क्वालिटी चेक किए जाते तो स्थिति यहां तक नहीं पहुंचती।

स्थानीय नागरिकों ने भी नाराजगी जताई और कहा कि **करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद अगर कुछ ही सालों में सड़क खराब हो जाए तो यह जनता के पैसे की बर्बादी है**।

तकनीकी पहलू और विशेषज्ञों की राय

विशेषज्ञों का कहना है कि सड़क पर दरारें और गड्ढे कई कारणों से हो सकते हैं। ड्रेनेज सिस्टम की खराबी, ओवरलोड ट्रैफिक, खराब एस्फाल्ट क्वालिटी, नियमित मेंटेनेंस की कमी।

हालांकि, अटल सेतु जैसे प्रोजेक्ट में इन सभी पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी था। विशेषज्ञों के अनुसार, **अगर समय-समय पर निरीक्षण होता तो इस स्तर की क्षति टल सकती थी**।

आर्थिक और सामाजिक असर

अटल सेतु की खराब स्थिति का असर सिर्फ यात्रियों की सुरक्षा तक सीमित नहीं है। पर्यटन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ने से स्थानीय लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बार-बार मरम्मत होने से सरकार पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है।

ठेकेदार पर जुर्माने का महत्व

ठेकेदार पर लगाया गया 1 करोड़ रुपये का जुर्माना केवल दंडात्मक कदम नहीं है, बल्कि यह एक **सख्त संदेश** भी है। आने वाले समय में अन्य ठेकेदारों को भी सतर्क रहना होगा। इससे सार्वजनिक परियोजनाओं में पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित होगी। जनता का भरोसा भी सरकार की कार्यप्रणाली पर कायम रहेगा।

भविष्य के लिए सबक

अटल सेतु प्रकरण ने स्पष्ट कर दिया है कि **बड़ी परियोजनाओं में निगरानी और क्वालिटी कंट्रोल बेहद जरूरी है**। नियमित निरीक्षण और मेंटेनेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। ठेकेदारों को केवल समय पर काम पूरा करने पर नहीं, बल्कि गुणवत्ता पर भी जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। तकनीकी निगरानी और थर्ड-पार्टी ऑडिट को और मजबूत करना होगा।

अटल सेतु का मामला सरकार और ठेकेदारों दोनों के लिए चेतावनी है। कुछ ही वर्षों में सड़क पर आई दरारें और गड्ढे यह साबित करते हैं कि निर्माण में गंभीर चूक हुई।

ठेकेदार पर लगाया गया 1 करोड़ का जुर्माना सही दिशा में उठाया गया कदम है। यह न केवल लापरवाह ठेकेदारों को सबक सिखाएगा, बल्कि भविष्य की परियोजनाओं में गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने की भी याद दिलाएगा।

अटल सेतु गोवा की पहचान है और इसे सुरक्षित और टिकाऊ बनाए रखना सरकार और ठेकेदारों दोनों की जिम्मेदारी है ।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsoever.